प्रसार भारती
आकाशवाणी शिमला
31.07.2025 / प्रादेशिक समाचार / 19.45 बजे

'' मुख्य समाचार''

- प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितम्बर तक शिमला में–सत्र के दौरान होंगी कुल 12 बैठकें।
- प्रदेश मंत्रिमण्डल ने शहरी निकायों के आगामी चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने को दी मंजूरी।
- टीजीटी और जेबीटी के अभ्यार्थियों को ऊपरी आयु सीमा में मिलेगी 2 वर्ष की एकमुश्त छूट।
- राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती से पहले उम्मीदवारों का डोप टैस्ट किया अनिवार्य–नए कर्मचारियों को देना होगा चिट्टे का सेवन न करने का शपथ पत्र।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर भू–स्खलन से अवरूद्ध सड़कों को खोलने में नाकाम रहने का लगाया आरोप।

राज्य मंत्रिमण्डल

प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितम्बर तक शिमला में होगा। प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये मॉनसून सत्र करवाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान सदन की कुल 12 बैठकें होंगी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की संस्तुति के बाद विधानसभा सचिवालय द्वारा आज मॉनसून सत्र को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मॉनसून सत्र के दौरान 21 और 28 अगस्त को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के रूप में तय किया गया है।

बैठक में राज्य चयन आयोग द्वारा टी.जी.टी. और जेबीटी पदों के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यार्थियों को ऊपरी आयु सीमा में दो वर्ष की एकमुश्त छूट देने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने अनाथ बच्चों के लिए आई.टी.आई., पॉलीटैक्निक्स, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों सहित सभी सरकारी, सरकारी द्वारा वित्तपोषित और निजी तकनीकी संस्थानों में प्रति पाठ्यक्रम एक सीट आरक्षित करने का फैसला भी लिया।

राज्य मंत्रिमण्डल–2

मंत्रिमण्डल की बैठक में आगामी शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप प्रदान करने से पहले पिछड़े वर्ग की आबादी का सही डेटा एकत्र करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई।

बैठक में दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 2 सौ 90 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। मंत्रिमण्डल ने राज्य सचिवालय में विधि अधिकारी अंग्रेजी के 5 और विधि अधिकारी हिन्दी के 2 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। हाल ही में मॉनसून की भारी वर्षा के कारण राहत शिविरों में रह रहे बेघर परिवारों को किराए के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को 5 हजार रूपए और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रूपए प्रतिमाह की दर से अधिकतम 6 माह तक किराया सहायता प्रदान की जाएगी।

डोप टैस्ट

राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती से पहले उम्मीदवारों का डोप टैस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि नए भर्ती होने वाले सभी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे चिट्टे का सेवन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशे की रोकथाम के लिए गम्भीरता से काम कर रही है और हर जिले में नशा मुक्ति केन्द्र खोलने का फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नशे की रोकथाम के लिए पंचायत स्तर पर पुलिस कांस्टेबल के साथ आशा कार्यकर्ताओं ओर पंचायत सहायक की टीम गठित होगी।

जो भी पुलिस में भर्ती होगी, उसमें पहली स्टेज पर डोप टेस्ट, चिट्टा का टेस्ट किया जाएगा। मेनली चिट्टा का टेस्ट किया जाएगा और उसके बारे में हमने विस्तृत रिपोर्ट मंगाई है पंचायतों में पांच और छह पंचायत पर एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगेगी, एक आशा वर्कर की ड्यूटी लगेगी और एक पंचायत सेक्रेटरी को उसकी कार्य प्रणाली में उसको सम्मिलित किया जाएगा, पूरी रिपोर्ट्स मंगाई जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार की रिपोर्ट्स है। उसमें कई जगह भांग प्राचीन काल से वहां उगाते आ रहे हैं, नशे में शराब भी आती है, सेवन भी आता है तो हमने कहा कि हमारा पहला और प्रथम दायित्व यह बनता है जो चिट्टा आ रहा है जिसकी सबसे अधिक सप्लाई कहां से आती है उसको हमने तोड़ना है और किन व्यक्तियों के पास सप्लाई हो रही है उसको हमने तोड़ना है।

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए एक हजार नौ सौ 20 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय के साथ कुल 6 हजार पांच सौ 20 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमण्डल के निर्णयों के जानकारी देते हुये सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें बजट घोषणा के अनुरूप घटक योजना, एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के अंतर्गत 50 बहु–उत्पाद खाद्य विकिरण इकाईयां स्थापित करने के लिए एक हजार करोड रुपये शामिल है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025–26 से 2028–29 तक चार वर्षों की अवधि के लिए दो हज़ार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अनुदान सहायता–एन.सी.डी.सी को भी मंजूरी दी है।

जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर भारी वर्षा से अवरूद्ध सड़कों को खोलने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सराज सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों को खोलने के लिए कई दानी सज्जन जे.सी.बी. और एल.एन.टी. मशीनें दे रहे हैं जबकि कांग्रेस नेता आपदा में भी अवसर की तलाश कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज के देजी गांव में आपदा से 11 लोगों की मौत हुई लेकिन एक महीने बाद भी वहां लोकनिर्माण विभाग जे.सी.बी. मशीनें नहीं भेज पाया है। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि जो सड़कें लोगों के खर्चे से खुल चुकी हैं, कांग्रेस नेता उनके बिल अपने नाम पर बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का दबाव डाल रहे हैं।

सिकंदर कुमार

सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने राज्यसभा में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन स्तर और सामाजिक सुरक्षा में सुधार का मुद्दा पुरजोर ढंग से उठाया। इसके जवाब में केन्द्रीय श्रम व रोजगार राज्य मंत्री शोभा कारान्दलाजे ने बताया कि केन्द्र सरकार ने सभी क्षेत्रों मे रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष रूप से जोर दिया गया है।

राजीव भारद्वाज

सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने आज लोकसभा में कांगड़ा जिले में नूरपुर की बहुउद्देशीय फिना सिंह सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने का मुद्दा उठाया। इस पर केन्द्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने बताया कि इस परियोजना को अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि फिना सिंह सिंचाई परियोजना को केन्द्र सरकार की ओर से 2 सौ 82 करोड़ 47 लाख रूपए की राशि प्रदान की जाएगी।

मौसम

प्रदेश के अनेक भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम आज भी रूक–रूक कर जारी रहा। भूस्खलन के कारण राज्य में अभी भी 2 सौ 91 सड़कें यातायात के लिए अवरूद्ध हैं। इसके अलावा 4 सौ 16 बिजली ट्रांसफार्मर और 2 सौ 19 पेयजल योजनाएं भी ठप्प हैं। वर्षा से जुड़ी घटनाओं में राज्य में एक सौ 73 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 36 लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक राज्य के अनेक भागों में भारी वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया है।

जनऔषधि केन्द्र

केन्द्रीय उर्वरक व रसायन राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत देश में वर्ष 2023–24 और 2024–25 के दौरान लगभग 3 हजार 4 सौ 93 करोड़ रूपए की दवाईयां जनऔषधि केन्द्रों के माध्यम से बेची गई हैं। राज्यसभा में सांसद इंदु गोस्वामी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 30 जून तक देशभर में कुल 16 हजार 9 सौ 12 जनऔषधि केन्द्र खोले गए हैं और इनके माध्यम से दवाईयां व चिकित्सा उपकरण 50 से 80 फीसदी सस्ती दरों पर बेचे जा रहे हैं।

'' मुख्य समाचार एक बार फिर''

- प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितम्बर तक शिमला में–सत्र के दौरान होंगी कुल 12 बैठकें।
- प्रदेश मंत्रिमण्डल ने शहरी निकायों के आगामी चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने को दी मंजूरी।
- टीजीटी और जेबीटी के अभ्यार्थियों को ऊपरी आयु सीमा में मिलेगी 2 वर्ष की एकमुश्त छूट।
- राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती से पहले उम्मीदवारों का डोप टैस्ट किया अनिवार्य–नए कर्मचारियों को देना होगा चिट्टे का सेवन न करने का शपथ पत्र।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर भू–स्खलन से अवरूद्ध सड़कों को खोलने में नाकाम रहने का लगाया आरोप।